

दैनिक

रोकथोक लेखनी

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App



महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ईद-ए-मिलाद के अवसर पर

29 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने 29 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है क्योंकि गुरुवार को ईद-ए-मिलाद और अनंत चतुर्दशी एक साथ पड़ रही है। शांतिपूर्ण उत्सवों को सुविधाजनक बनाने और धार्मिक जुलूसों

राज्य सरकार ने शुक्रवार 29 सितंबर को ईद-ए-मिलाद के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, "मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा। "यह निर्णय अनंत चतुर्दशी

और ईद-ए-मिलाद एक ही दिन यानी कल 28 तारीख को पड़ने के मद्देनजर लिया गया है।" अनंत चतुर्दशी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भव्य जुलूसों और भगवान गणेश की मूर्तियों के विसर्जन समारोह के साथ मनाया जाता है। ईद-ए-मिलाद, जो पैगंबर मुहम्मद के जन्म का प्रतीक है और प्रार्थनाओं, दावतों और समारोहों के साथ मनाया जाता है, इस वर्ष अनंत चतुर्दशी के साथ मेल खाता है। "आप सभी को ईद-ए-मिलाद की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। शिंदे ने मराठी में अलग सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शुक्रवार 29 सितंबर 2023 को ईद-ए-मिलाद के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।



मुंबई में गणेश प्रतिमा विसर्जन ड्यूटी पर 19,000 से अधिक पुलिसकर्मी लगाये गये

मुंबई : गणेशोत्सव के आखिरी दिन 28 सितंबर को अनंत चतुर्थी पर मूर्तियों के विसर्जन के लिए निकाले जाने वाले जुलूस के मद्देनजर किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए मुंबई पुलिस अधिकारियों समेत 19,000 से अधिक कर्मियों को तैनात कर रही है। ईद-ए-मिलाद के लिए भी ऐसा ही सुरक्षा इंतजाम किया जाएगा। इस मौके पर शुक्रवार को जुलूस निकाला जाएगा। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने 1,337 लाइफगार्ड तैनात किये हैं जिनमें 1035 को 69 प्राकृतिक जलाशयों पर तैनात किया गया है जबकि 302 को करीब 200 कृत्रिम तालाबों के आसपास पदस्थ किया गया है। बीएमसी ने प्राकृतिक विसर्जन स्थलों पर 53 मोटरबोट लगाये हैं। कई मुस्लिम संगठनों और धार्मिक नेताओं ने अनंत चतुर्थी के



मद्देनजर बृहस्पतिवार के बजाय शुक्रवार को ईद-ए-मिलाद जुलूस निकालने का फैसला किया है। पुलिस ने उनसे यह अपील की थी। एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा ड्यूटी पर लगाये गये पुलिसकर्मियों में 16,250 कांस्टेबल, 2,866 अधिकारी, 45 सहायक पुलिस आयुक्त, 25 पुलिस उपायुक्त, आठ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एवं अन्य अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा राज्य रिजर्व पुलिस बल के 35 प्लाटून, त्वरित कार्रवाई बल की एक कंपनी, त्वरित प्रतिक्रिया बल के साथ ही होमगार्ड के जवान भी अहम स्थानों पर मौजूद रहेंगे।

महाराष्ट्र में फिर गरमाएगा मराठा आरक्षण मुद्दा, 30 सितंबर से समर्थन जुटाएंगे नेता

- ✘ मराठा आरक्षण के समर्थक मनोज जरांगे-पाटिल ने किया ऐलान
- ✘ जरांगे मराठा आरक्षण के मुद्दे पर कई जिलों का दौरा करेंगे
- ✘ मैं मराठों के लिए नौकरियों और शिक्षा में कोटा के मुद्दे पर चर्चा करूंगा

जालना: महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाने वाला है। मराठा आरक्षण के समर्थक मनोज जरांगे-पाटिल ने बड़ा ऐलान किया है। जरांगे ने घोषणा की है कि वह समुदाय के लिए आरक्षण के मुद्दे पर समर्थन जुटाने के लिए राज्य के कई जिलों के 12 दिवसीय दौरे पर निकलेंगे। मनोज जरांगे-पाटिल ने पत्रकारों को बताया कि मैं मराठों के लिए नौकरियों और शिक्षा में कोटा के मुद्दे पर चर्चा करने, उन्हें अपना रुख समझाने और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक जन-संपर्क अभियान शुरू करूंगा। राज्य की राजनीति में भूचाल लाने के बाद मराठा नेता की यह पहली बड़ी कार्रवाई है। लेकिन, 14 सितंबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और जालना में आंदोलन स्थल अंतरावली-सारती गांव का दौरा करने वाले अन्य लोगों के हाथों उन्होंने अपनी 17 दिनों की लंबी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। उस समय राज्य सरकार ने कहा था कि उसने जरांगे-



पाटिल की अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन उन्होंने मराठा कोटा लागू करने के लिए और समय देने का अनुरोध किया था, जो किसी भी कानूनी चुनौती का सामना कर सकता था। राज्य ने पूरे मामले पर गौर करने के लिए एक पैनल भी नियुक्त किया, जिसमें मराठों के लिए ओबीसी कोटा में उन्हें शामिल करने पर विचार किया गया, जैसा कि जरांगे-पाटिल ने मांग की थी। जरांगे-पाटिल ने यह भी चेतावनी दी थी कि यदि मराठा आरक्षण की मांगें राज्य सरकार द्वारा पूरी नहीं की गईं, तो वे पूरे राज्य में रिले-भूख हड़ताल और अन्य प्रकार के आंदोलन शुरू करेंगे। आगामी लोकसभा, राज्य में निकाय और विधानसभा चुनावों में इस मुद्दे के संभावित असर से चिंतित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने बार-बार आश्वासन दिया है कि सरकार किसी अन्य समुदाय के साथ अन्याय किए बिना मराठों को कोटा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

ड्रग सप्लायर कैलाश राजपूत के भाई कमल को मुंबई क्राइम ब्रांच ने वसई से पकड़ा

मुंबई : मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल (एईसी) ने भारतीय ड्रग सप्लायर कैलाश राजपूत के भाई कमल राजपूत को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस ने कहा कि कमल के लिए लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद उसे वसई से गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने कहा कि कमल को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया और 30 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, कमल भारत में कैलाश का ड्रग कारोबार देखता था। इससे पहले मई में, मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल ने अली असगर परवेज शिराजी को मुंबई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था, जो भारत में ड्रग्स के प्रमुख आपूर्तिकर्ता कैलाश राजपूत का करीबी सहयोगी है। पुलिस ने आगे बताया कि आरोपी अली असगर शिराजी मुंबई से दुबई भागने की फिराक में था। आरोपी के खिलाफ मुंबई पुलिस में छह मामले दर्ज हैं और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। एईसी ने शिराजी समेत राजपूत के करीबी सहयोगियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था, जिसे अब दो महीने की तलाश के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है।



ढेकेदार 37 प्रतिशत कम दर पर काम करने को हुआ तैयार

मुंबई : ढेकेदार बीएमसी पर मेहरबान हो गए हैं। ढेकेदार अनुमानित लागत से 37 प्रतिशत कम पर प्रमुख पाइपलाइन के साथ-साथ गार्डन और साइकिल ट्रैक का रखरखाव करने के लिए तैयार है। इस पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने सदेह जताया है। इनका कहना है कि ढेकेदार 63 प्रतिशत लागत पर काम करने को कैसे तैयार हो

सकता है। इससे काम की क्वालिटी क्या होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बीएमसी ने पाइपलाइन के पास साइकिल ट्रैक के साथ गार्डन विकसित किया है। गार्डन और साइकिल ट्रैक के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट जून में समाप्त हो गया। अब बीएमसी ने गार्डन और साइकिल ट्रैक के रखरखाव के लिए नए ढेकेदार को नियुक्त करने का फैसला किया



है। बीएमसी ने मुख्य पाइपलाइन के साथ-साथ 15 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक के लिए टेंडर मंगाया था। बीएमसी ने 1 साल के रखरखाव के लिए 5.91 करोड़ रुपये की लागत

का अनुमान लगाया था। जबकि सबसे कम टेंडर 3.72 करोड़ रुपये में भरा गया है। जो बीएमसी की अनुमानित कीमत से 37.12 फीसदी कम है। बीएमसी के एक अधिकारी ने कहा कि निर्देश के अनुसार हमने सबसे कम दर पर टेंडर भरने वाले ढेकेदार को चुना है। इसमें साइकिल ट्रैक, सर्विस रोड और गार्डनिंग का

रखरखाव शामिल है। बीएमसी ने विभिन्न स्थानों पर कुल 15 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक बनाया है। मुलुंड से सहार के बीच मुख्य पाइप लाइन के साथ 7 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक और गार्डन है। घाटकोपर से सायन के बीच 5 किलोमीटर और पवई से साकीनाका के बीच 3 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक बीएमसी ने बनाया है।

संपादकीय / लेख



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

संकट में टेलीकॉम सेक्टर

टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने हाल ही में एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की है, जिससे पता चलता है कि सब्सिडी देने के बावजूद, भारत में दूरसंचार हार्डवेयर का निर्माण न सिर्फ चीन बल्कि वियतनाम की तुलना में भी महंगा है। रिपोर्ट के अनुसार, 'इंडियन नेटवर्किंग और टेलीकॉम इक्विपमेंट मैनुफैक्चरिंग (नाटेम)

कंपनियों को चीन में काम करने वाली कंपनियों की तुलना में महंगे निर्माण का सामना करना पड़ता है। यदि इन्हें 'पीएलआई' के लाभ नहीं दिए जाएं तो इनकी लागत कम से कम ४ फीसदी और बढ़ जाएगी। ये ऐसे उत्पाद हैं, जिनका उपयोग ऑपरेटरों द्वारा अपने दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है।

स्मार्टफोन आज हर हाथ की जरूरत बन चुके हैं। इनके निर्माण में चीन दुनिया में टॉप पोजिशन पर है। वहां पर काफी सस्ते फोन व दूरसंचार उपकरणों से जुड़े हार्डवेयर बनाए जाते हैं, इसीलिए दुनिया की सभी प्रमुख फोन निमाता कंपनियां या तो अपने फोन चीनी कंपनियों से बनवाती हैं या चीन से फोन के हार्डवेयर का आयात करके असेंबल करवाती हैं। मोदी सरकार ने भी देश में मेक इन इंडिया जैसी स्कीम चलाकर उद्योग-धंधों को बढ़ावा दिया है। पर जहां तक दूरसंचार उपकरणों के हार्डवेयर का सवाल है तो चीन के मुकाबले यहां इसकी राह काफी 'हार्ड' यानी मुश्किल है। भारत में इसका निर्माण १३ फीसदी महंगा है। ऐसा तब है, जब सरकार इनके लिए पीएलआई योजना के तहत सब्सिडी दे रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'जबकि दूरसंचार विभाग ने ४२ कंपनियों को उत्पादों की 'टाइप २' श्रेणी में सब्सिडी दी गई है, इसके बावजूद परिणाम सीमित हैं। सब्सिडी योजना के पहले वर्ष के दौरान निर्यात में केवल ३० करोड़ की वृद्धि हुई। चीन, वियतनाम और भारत जैसे देशों के बीच निर्माण लागत में असमानता के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए, ट्राई ने पाया कि चीन 'हाई-एंड न्यू-टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज (एचएनटीई)' और 'मेड इन चाइना २०२५' जैसे कार्यक्रम चलाता है जो तकनीकी क्षेत्रों में लगी कंपनियों को कई लाभ प्रदान करते हैं। ये कार्यक्रम अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) में निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। वे घटिया उत्पादन करनेवाले निमाताओं को बेहतर उत्पादन करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह वियतनाम निमाताओं को कम कॉर्पोरेट टैक्स और आयात शुल्क जैसे प्रोत्साहन प्रदान करता है। सब्सिडी योजनाएं तैयार माल पर दी जाती हैं। इसके अलावा, भारत आयात शुल्क बढ़ाकर तैयार उत्पादों के आयात पर अंकुश लगाने की कोशिश करता है। इस प्रकार, नियामक प्राधिकरण ने केंद्र सरकार को पीएलआई योजनाओं से आगे बढ़ाने की सिफारिश की है।

+91 99877 75650

editor@rokhoklekhaninews.com

Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

रंग-कोडित पास, आधुनिक प्लाजा : मंत्रालय में आगंतुकों को नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार का उपाय

महाराष्ट्र: आगंतुकों की आमद को नियंत्रित करने और मंत्रालय में विरोध प्रदर्शन और आत्महत्या के प्रयासों की घटनाओं को संबोधित करने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने कड़े उपायों की एक श्रृंखला शुरू करने का आदेश जारी किया है। इन उपायों का उद्देश्य सचिवालय के भीतर दैनिक प्रशासनिक कार्यों की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करते हुए प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।

मंत्रालय में प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के नए उपाय:

रंग-कोडित और आरएफआईडी पास: सरकार ने आगंतुकों के लिए रंग-कोडित और आरएफआईडी (रेडियो-फ्रीक्वेंसी पहचान) पास जारी करने की शुरुआत की है। रंग कोड प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आगंतुकों को प्रवेश के समय संकेतित विशिष्ट मंजिलों पर ही निर्देशित किया जाएगा, जिससे इमारत के भीतर अनावश्यक आवाजाही कम हो जाएगी। ये पास मंत्रालय में प्रवेश और निकास के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

पहले से बुक किए गए टाइम स्लॉट: व्यवस्था बनाए रखने और आगंतुकों की संख्या को सीमित करने के लिए, नई प्रणाली नियुक्तियों के लिए टाइम



स्लॉट की प्री-बुकिंग को अनिवार्य करती है। आगंतुकों को उनके प्रवेश पास के आधार पर विशिष्ट विभाग या मंजिल आवंटित किए जाएंगे। रोमिंग पर प्रतिबंध: आगंतुकों को उनके प्रवेश पास में निर्दिष्ट के अलावा विभागों या मंजिलों के भीतर स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आगंतुकों की संख्या का प्रबंधन: आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि मंत्रालय में औसतन 3,500 आगंतुक आते हैं, कैबिनेट बैठक के दिनों में यह संख्या 5,000 तक बढ़ जाती है। सरकार का लक्ष्य आगंतुकों के प्रवाह को विनियमित करके इस मुद्दे का समाधान करना है।

उन्नत सुरक्षा उपाय: ऊपरी मंजिल से कूदने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों की पिछली घटनाओं के जवाब में, मंत्रालय की दूसरी मंजिल पर एक सुरक्षा जाल स्थापित किया गया था। हालांकि, इसने प्रदर्शनकारियों को अपने प्रदर्शनों के लिए नेट का

उपयोग करने से नहीं रोका। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने का फैसला किया है। सरकार सुरक्षा बढ़ाने के लिए खुले स्थानों, गलियारों और खिड़कियों में स्टील की रस्सियाँ लगाने की योजना बना रही है। इसके अतिरिक्त, आगंतुकों को प्रवेश पर 10,000 रुपये से अधिक नकद ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

आधुनिक प्लाजा निर्माण: मंत्रालय के गार्डन गेट के पास एक आधुनिक प्लाजा का निर्माण किया जाएगा। यह प्लाजा आगंतुकों की सुविधा को बढ़ाते हुए पास काउंटर, वेटिंग रूम, बैग लॉकर और स्कैनर जैसी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित होगा।

केंद्रीकृत पत्राचार: आदेश में कहा गया है कि संबंधित विभाग को पत्राचार अब एक केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, आदेश में मंत्रालय में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पुलिस उपायुक्त से दैनिक आगंतुक सीमा की रूपरेखा बताते हुए एक महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने वर्तमान ड्रोन सुरक्षा प्रणाली को हुए नुकसान के कारण वार्षिक रखरखाव अनुबंध देने का निर्णय लिया है।

मध्य रेलवे 28 सितंबर को मुंबई-कामाख्या वन-वे सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाएगा



मुंबई: मध्य रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए मुंबई से कामाख्या तक विशेष शुल्क पर एक तरफा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है।

01055 स्पेशल गुरुवार 28 सितंबर को दोपहर 1 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रवाना होगी और तीसरे दिन दोपहर 3.30 बजे कामाख्या पहुंचेगी।

हॉल्ट: कल्याण, नासिक रोड, भुसावला, मलकापुर, अकोला, नागपुर, गोंदिया, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, झारसुगुड़ा, राउरकेला,

चक्रधरपुर, टाटानगर, खड़गपुर, दनकुनी, बर्धमान, बोलपुर शांतिनिकेतन, रामपुरहाट, पाकुड़, मालदा टाउन, न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, हासीमारा, अलीपुरद्वार और न्यू बोंगाईगांव। संरचना: 5 एसी-3 टियर, 10 स्लीपर क्लास, एक पेंट्री कार और 5 सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड के ब्रेक वैन।

आरक्षण: विशेष शुल्क पर 01055 एकतरफा विशेष ट्रेन के लिए बुकिंग सभी पीआरएस स्थानों और वेबसाइट ६६६.१३.३३.३३ पर पहले से ही शुरू है।

महाराष्ट्र के नासिक में चार्ज हो रहा था मोबाइल, अचानक हुआ धमाका, तीन लोग घायल

महाराष्ट्र के नासिक जिले में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक चार्जिंग पर लगे मोबाइल फोन में जबदस्त धमाका हुआ। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि इससे पड़ोसी के घर की खिड़की के शीशे टूट गए, पास खड़ी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस बीच तीन लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। इसमें एक हालात गंभीर बताई जा रही है। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह हादसा बुधवार सुबह छह बजे नासिक जिले के उत्तमनगर इलाके में हुआ। घायलों की पहचान तुषार जगताप, बालकृष्ण सुतार और शोभा जगताप के रूप में हुई है। यह विस्फोट इतना तेज था कि एक घर भी क्षतिग्रस्त हो गया।

आसपास के घरों की खिड़कियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके की सूचना

के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस तरह का हादसा एक साल पहले यूपी के बरेली में भी हुआ था। यहां पर एक मोबाइल चार्जिंग के लिए लगा हुआ था कि तभी जोरदार ब्लास्ट हो गया। इसमें एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले एक महिला की मोबाइल धमाके में मौत हो गई थी। इस मामले में विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में यूजर्स को सतर्क रहने की जरूरत है। वे ज्यादा देर तक मोबाइल को चार्जिंग के लिए न लगाएं। इसके साथ अपनी बैटरी को चेक करते रहें।

अगर ये फूल रही है तो इसे तुरंत रिप्लेस कर दें। मोबाइल को ज्यादा चार्ज करने के दौरान अक्सर बैटरी फट जाती है। कई बार ये हीटअप होकर ब्लास्ट हो जाती है। इस कारण कई बड़े हादसे हो जाते हैं।

ट्रेलर ने मारी टक्कर और सबकुछ खत्म, ड्राइवर की गलती बनी युवक की मौत की वजह

रायगढ़: मुंबई गोवा हाइवे पर हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रायगढ़ जिले के नागोठाणे में एक भीषण हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। हाईवे पर तेज गति से आए ट्रेलर चालक ने शराब के नशे में सामने आ रही बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक पर सदेश सदानंद घाणेकर (उम्र 32) की मौत हो गई। युवक रत्नागिरी जिले के चिपलून तालुका के सावर्डे का रहने वाला है।

गणेशोत्सव के बाद वह दोबारा दोपहिया

वाहन से पैदल मुंबई जा रहे थे। मुंबई वडाला गणेश नगर में रहने वाला एक युवक है। सदेश काम के सिलसिले में मुंबई में रह रहा था। यह भीषण हादसा कंसाई गांव की सीमा में होटल नवरल के पास हुआ। ट्रेलर चालक नशे में था और सुकेली से नागोठाणे की ओर तेजी से गाड़ी चला रहा था। इस मामले में ट्रेलर चालक मध्य प्रदेश निवासी ओमप्रकाश रामलाल पटेल (उम्र 36 वर्ष) के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

राम भक्तों के लिए खुशखबरी, राम मंदिर में

रामलला की स्थापना की तारीख पक्की, समारोह में मोदी भी हुए शामिल

इस दुर्घटना की खबर सामने आते ही नागठाणे पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक पोमन और पुलिसकर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। सदेश सदानंद घाणेकर की हाल ही में दो साल पहले शादी हुई थी और वह अपनी नौकरी के लिए मुंबई वडाला गणेश नगर में रह रहे थे। वह अपनी मां, पिता और पत्नी को घर पर छोड़कर दोपहिया वाहन से मुंबई के लिए निकल गए। लेकिन दुर्भाग्य से सदेश का सफर आखिरी था।

मराठी में लगाना होगा साइनबोर्ड!

सुप्रीम कोर्ट ने दिया २ महीने का समय...

मुंबई : मुंबई में खुदरा व्यापारियों को मराठी में नए साइनबोर्ड लगाने के लिए २ महीने का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार की ओर से पिछले वर्ष लागू उस नियम की संवैधानिक चुनौती पर विचार करने के लिए भी सहमत हो गया, जिसमें कहा गया कुछ शर्तों के साथ हर बड़ी और छोटी दुकान के बाहर मराठी साइनबोर्ड लगाना आवश्यकता है। न्यायमूर्ति बीवी नागराज और न्यायमूर्ति उज्वल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि मराठी साइनबोर्ड लगाने से दुकानदारों को ही फायदा मिलेगा, क्योंकि दशहरा और दीपावली पर्व नजदीक हैं।



महाराष्ट्र में हैं, आपको मराठी साइनबोर्ड होने का लाभ नहीं पता? नए साइनबोर्ड को आपके व्यावसायिक व्यय का हिस्सा बनाया जा सकता है। अगर हम आपको (मुंबई) हाईकोर्ट भेजते हैं तो आप पर भारी जुमाना लगाया जाएगा।

का नियम मराठी को अनिवार्य बनाता है। इसके मुताबिक, अक्षरों का फॉन्ट एक ही होना चाहिए और इसे साइनबोर्ड पर किसी भी दूसरी भाषा के ऊपर लिखना होगा। दुकानदारों की ओर से कहा गया कि मौजूदा साइनबोर्ड को नए से बदलने में धन भी काफी खर्च होगा। इस खंडपीठ ने कहा कि 'आप मराठी भाषा में बोर्ड क्यों नहीं लगा सकते? नियम अनुपालन करें। कर्नाटक में भी यही (नियम) है। अन्यथा, वे मराठी फॉन्ट को इतना छोटा, अंग्रेजी को इतना बड़ा रखेंगे। यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन क्या है? अब दिवाली, दशहरा से पहले मराठी साइनबोर्ड लगाने का समय आ गया है। आप

न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि नए बोर्ड बनाने वालों के लिए अब रोजगार के अवसर हो सकते हैं। खंडपीठ ने मराठी साइनबोर्ड लगाने के लिए दो महीने का समय देते हुए मामले की सुनवाई दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के याचिकाकर्ता-खुदरा विक्रेताओं के संघ को कानूनी शुल्क पर पैसा खर्च करने की बजाय एक साधारण साइनबोर्ड में निवेश करने की सलाह दी थी। खंडपीठ ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे को अंधराष्ट्रीयता या विदेशियों के प्रति घृणा के रूप में चित्रित करने से बचना चाहिए।

मुंबई के खुदरा व्यापारियों के संघ की याचिका पर सुनवाई के लिए वकील मोहिनी प्रिया फेडरेशन की ओर से पेश हुई। उन्होंने कहा कि दुकानदार मराठी साइनबोर्ड रखने के खिलाफ नहीं हैं, मगर राज्य सरकार

नार्वेकर को बीच के दिनों में किसने निर्देशित किया और उन्हें क्या निर्देशित किया गया...

इसकी जानकारी ली जानी चाहिए - अंबादास दानवे

मुंबई : विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने गद्दर विधायकों की अयोग्यता की सुनवाई को लेकर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर जमकर निशाना साधा। नार्वेकर को बीच के दिनों में किसने निर्देशित किया और उन्हें क्या निर्देशित किया गया, इसकी जानकारी ली जानी चाहिए, ऐसा दानवे ने कहा। इसके साथ ही उन पर किसका दबाव है, ऐसा सवाल भी उन्होंने उपस्थित किया। उन्होंने कल नागपुर में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब ने उक्त बातें कहीं। अंबादास दानवे ने कहा, 'विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर एक प्राधिकारी (न्यायाधिकरण) हैं। इसलिए उनसे केवल अयोग्यता अधिनियम की व्याख्या करने की अपेक्षा की जाती है, जो मतलब निकालना चाहे निकाले। व्याख्या हमारे पक्ष में रखें या हमारे खिलाफ रखें।' हमारे पक्ष में अर्थ लगाओ, ऐसा मेरा मानना नहीं है।



मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति बन रही है कि उन्हें कानून की कसौटी पर ही फैसला देना होगा।

नार्वेकर अभी भी इसमें लगे हुए हैं कि कैसे समय पास किया जाए। अंबादास दानवे ने कहा, 'हम परिणाम की तारीखों की घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि रिजल्ट की तारीखें अपने हाथ में नहीं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द फैसला सुनाने का निर्देश दिया। ११ मई २०२३ को यह फैसला आने के बाद अब सितंबर महीना खत्म हो गया है, लेकिन इस मामले की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। अध्यक्ष राहुल नार्वेकर

अभी भी इसमें लगे हुए हैं कि किसी तरह भी इस प्रक्रिया को टाला जाए, इस मामले में राजनीति की जा रही है। अध्यक्ष पर किसी का दबाव है क्या? राहुल नार्वेकर ने सुनवाई से पहले इस दौरान किन-किन से मुलाकात की, क्या-क्या मार्गदर्शन लिया इसकी एक बार जानकारी लेनी चाहिए। वे कहते हैं कि हम पर दबाव डालते हैं, लेकिन उन पर दबाव किसका है? उन पर केंद्र के भाजपा नेताओं या राज्य के भाजपा नेताओं का दबाव है? वे किसके दबाव में काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी आम जनता को पता चलनी चाहिए, ऐसा दानवे ने कहा।

मुंबई को टाणे से जोड़ने वाली सबसे लंबी मेट्रो लाइन के निर्माण का काम पटरी पर

मुंबई : महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) मुंबई को टाणे से जोड़ने वाली सबसे लंबी मेट्रो लाइन के निर्माण का काम पटरी पर आ रहा है। डिपो के निर्माण के लिए एमएमआरडीए की तरफ से इस मार्ग के लिए ठेकेदार को नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि ३२.३२ किलोमीटर लंबे मुंबई मेट्रो रूट ४ और ४ए प्रोजेक्ट के लिए टाणे के मोघरपाड़ा में एक डिपो बनाया जाएगा।



२०२२ को ई-टेंडर निकाला गया था। जिसके अनुसार, एमएमआरडीए ने इस माध्यम से प्रस्तुत सबसे कम कीमत ९,०५,००,००,०००/- की निविदा को स्वीकार कर उसे मंजूरी दी।

मेट्रो रूट ४ और ४ए (वडाला-घाटकोपर-मुल्ड-टाणे-कासरवडवली-गायमुख) पर मोघरपाड़ा में मेट्रो कार डिपो के निर्माण के लिए २१ अक्टूबर,

मोघरपाड़ा में करीब ४२.२५ हेक्टेयर जमीन पर डिपो बनाया जाएगा। डिपो में स्टेबलिंग यार्ड, ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर और प्रशासनिक भवन, रखरखाव और

वर्कशॉप बिल्डिंग, सबस्टेशन, स्टाफ क्वार्टर, पाइपलाइन, भूमि विकास स्थल, सड़क, डिपो को जोड़ने वाला पुल, अंडरग्राउंड वर्क सहित डिपो बेसिक इंफ्रस्ट्रक्चर का निर्माण शामिल है। मोघरपाड़ा में स्थापित होने वाले डिपो में ६४ स्टेबलिंग लाइनें होंगी, जिनमें से ३२ का उपयोग फिलहाल किया जाएगा जबकि ३२ लाइनों को उपयोग भविष्य में किया जाएगा। साथ ही

१० इंस्पेक्शन लाइनें व १० वर्कशॉप लाइनें भी होंगी।

मुंबई मेट्रो रूट ४ का ५८ प्रतिशत और ४ए का ६१ प्रतिशत निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जिसके बाद अब मेट्रो लाइन बिछाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। लाइन मेट्रो ४ और ४ए (वडाला-कासरवडवली गायमुख) के लिए लाइनों के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए, मुल्ड फायर स्टेशन से गायमुख स्टेशन और डिपो को गायमुख स्टेशन से जोड़ने वाली साइडिंग और बैलेस्टिक के लिए मई अपूर्वकृति इंफ्रस्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड का चयन किया गया है।

अंधेरी में छापा, २२ किलो नशीला पदार्थ बरामद



मुंबई : पिछले पिछले कई सालों से देशी शराब और फिर अन्य नशीला पदार्थ बेचने वाली एक महिला अपने परिवार के साथ अंधेरी पूर्व धोबीघाट में रहती थी। पहले यह लोग देशी शराब का धंधा करते थे, उसके बाद गांजा बेचने लगे थे। स्थानीय पुलिस की शह पर कई सालों से अंधेरी का यह इलाका नशे की लत की सामग्री उपलब्ध कराने का अड्डा माना जाता है। यहां हाल ही में एक युवती का विवाह ऐसे युवक से हुआ था जिसकी मां नशे का व्यापार करनेवाले लोगों की मुखिया थी। जब इस बात का पता बहू को चला तो वह अपने पति के साथ किराए का घर लेकर दूसरी जगह रहने लगी।

कहें या कुछ और जिस समय खिचड़ी बन रही थी ठीक उसी समय पुलिस उपायुक्त की स्पेशल टीम ने अंधेरी में छापा मारा और २२ किलो नशीला पदार्थ बरामद किया। ड्रग बेचने के मामले में पुलिस ने बरखा इंद्रकर, विजय रमेश, सारिका इंद्रकर और रागिनी सागर नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं मौके से गौरी नवलेकर जो इस नशे की दुनिया की मुखिया थी, भागने में सफल रही। हालांकि, पुलिस की टीम ने उसे बाद में हिरासत में ले लिया। बता दें कि गौरी नवलेकर की बहू रागिनी सागर नवलेकर ही वह बहू है जो खिचड़ी के चक्कर में इस मामले में फंस गई। इस मामले में पुलिस ने रागिनी नवलेकर को भी ड्रग तस्कर बताकर गिरफ्तार किया। इसी परिवार से जुड़े अन्य सूत्रों की मानें तो पुलिस को गौरी के घर से भी काफी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ था।

एक दिन बहू अपने पति के साथ अपने सास के घर आईं। जिसके बाद बहू ने अपनी सास से खिचड़ी खाने की इच्छा जाहिर की। अब इसे संयोग

वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई नियमावली जारी...

मुंबई : मुंबई मनपा अंतर्गत हर जगह लगातार हो रहे निर्माण के कारण मुंबई में एक बार फिर से वायु गुणवत्ता खराब हो रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पर मुंबई का प्रदर्शन लगातार खराब हो रहा है। इसको लेकर मनपा बिल्डिंगों पर तलख हो गई है। मनपा के डेवलपमेंट प्लानिंग विभाग ने



वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई नियमावली जारी की है।

साथ वायु प्रदूषण की समस्या फिर से शुरू हो गई है। चार दिन पहले मुंबई में वायु प्रदूषण का प्रमाण बढ़ा हुआ था। पिछले वर्ष अक्टूबर व नवंबर महीने में मुंबई में प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसलिए मनपा ने आगामी समस्या को देखते हुए सुधारात्मक उपायों को लेकर अभी से काम शुरू कर दिया है, ऐसा दावा

मनपा अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है।

१५ सितंबर को मुख्य अभियंता सुनील राठौड़ ने एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें निर्माण स्थलों पर समय-समय पर जांच करने और दोषी डेवलपर्स को काम रोकने की नोटिस देने जैसी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

गोपीनाथ मुंडे की बेटी के साथ बीजेपी का अन्याय: पंकजा मुंडे को सोच समझकर उचित फैसला लेना चाहिए



महाराष्ट्र: गोपीनाथ मुंडे ने महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा बनाया। लेकिन आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक बड़े नेता ने आरोप लगाया है कि उनकी ही बेटी पंकजा मुंडे के साथ बीजेपी में गलत व्यवहार किया जा रहा है। इस नेता ने पंकजा को सोच-समझकर सही फैसला लेने

की सलाह भी दी है। बीड में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे की चीनी फैक्ट्री पर जीएसटी विभाग की कार्रवाई से राजनीतिक गलियों में हलचल मच गई है। पंकजा ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाया है। 7-8 चीनी मिलों की मदद के लिए सरकार को प्रस्ताव

भेजा गया था। इसमें मेरी फैक्ट्री का नाम भी था। लेकिन मेरी फैक्ट्री को छोड़कर बाकी फैक्ट्रियों की मदद की गई। इस मामले में, मेरी फैक्ट्री को बाहर रखा गया?, उसने कहा। पंकजा को फैसला करना चाहिए पंकजा के बयान के बाद प्रारंभिक संगठन के नेता विधायक बच्चू कडू

ने दावा किया कि पंकजा मुंडे की शिव शक्ति संवाद यात्रा के कारण ही यह कार्रवाई की गई है। उनके दावे के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दावा किया है कि बीजेपी पंकजा मुंडे के साथ अन्याय कर रही है। पंकजा मुंडे को बीजेपी में भारी अन्याय का

सामना करना पड़ रहा है। गोपीनाथ मुंडे ने महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा बनाने का काम किया। लेकिन अब पार्टी के जरिए उनकी ही बेटी के साथ अन्याय हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, अब उन्हें सोच समझकर उचित निर्णय लेना चाहिए।

अनिल देशमुख ने ये भी खुलासा किया कि इस वक्त उन्हें बीजेपी से ऑफर मिला है। मेरे खिलाफ ईडी की कार्रवाई शुरू होने के बाद बीजेपी ने मुझे मदद की पेशकश की। अगर मैंने उस वक्त समझौता कर लिया होता तो मुझे कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा, लेकिन तब हमारी सरकार गिर जाती।

एनएमएमसी ने पूरे शहर में विसर्जन स्थलों से 48 टन से अधिक गीला प्रसाद एकत्र किया



नवी मुंबई: नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी) पहले ही शहर भर में 141 कृत्रिम और 22 पारंपरिक विसर्जन स्थलों से 48 टन से अधिक प्रसाद (गीला निर्माल्य) एकत्र कर चुका है। नागरिक निकाय ने एकत्र किए गए प्रसाद को तुर्बे अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र में अलग से रखा, जहां इन प्रसाद को वैज्ञानिक तरीके से उर्वरक में संसाधित किया जाएगा। पर्यावरणीय पहलू को ध्यान में रखते हुए, नागरिक निकाय, हर दूसरे वर्ष की तरह, गीले प्रसाद जैसे माला, फूल, दुर्वा, तुलसी, शमी, फलों के छिलके आदि का पुनर्चक्रण करता

है। 22 पारंपरिक विसर्जन स्थलों के साथ-साथ 141 कृत्रिम विसर्जन स्थलों पर अलग-अलग निर्माल्य कलश स्थापित किए गए थे। विसर्जन स्थल नगर निकाय ने प्रत्येक विसर्जन स्थल पर अलग-अलग वाहन भी तैनात किए थे और सम्मानजनक तरीके से प्रसाद एकत्र किया था। एनएमएमसी के टोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमने अब तक कुल 48 टन और 500 किलोग्राम गीला निर्माल्य या प्रसाद एकत्र किया है।" विसर्जन के सातवें दिन, नगर निकाय ने सभी स्थलों से लगभग 3 टन और 915 किलोग्राम प्रसाद एकत्र किया। 10वें दिन के विसर्जन या अनंत चतुर्दशी के लिए, नगर निकाय पर्याप्त व्यवस्था करेगा क्योंकि बड़ी मात्रा में प्रसाद विसर्जित होने की उम्मीद है।

17.5 लाख रुपये मूल्य का मेफेड्रोन जब्त; 3 व्यक्ति गिरफ्तार



नवी मुंबई: एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि पुलिस ने नवी मुंबई में 17.5 लाख रुपये मूल्य की प्रतिबंधित दवा मेफेड्रोन पाउडर जब्त किया है और इस सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) ने एक गुप्त सूचना के बाद मंगलवार को बेलापुर खाड़ी के किनारे जाल बिछाया और तीन लोगों को देखा। सीबीडी बेलापुर पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कहा कि जांच के

दौरान, पुलिस ने उनके कब्जे से 175 ग्राम मेफेड्रोन पाउडर, एक सिंथेटिक उत्तेजक पदार्थ बरामद किया। उन्होंने बताया कि तीन लोगों को मंगलवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें पड़ोसी मुंबई के दो लोग भी शामिल थे और जिनकी उम्र 18 से 32 साल के बीच थी। पुलिस ने कहा कि उन पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

हत्या का दोषी पैरोल से बाहर आने के 12 साल बाद तेलंगाना से पकड़ा गया

मुंबई: एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 39 वर्षीय हत्या का दोषी, जो पैरोल खत्म होने के बाद पिछले 12 वर्षों से फरार था, को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने तेलंगाना से गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि दोषी अशोक हनुमंत काजेरी उर्फ वी शिवा नरसीमुल्लू अपना नाम और पहचान बदलकर तेलंगाना के महबूबनगर शहर में रह रहा था।



अधिकारी ने कहा, उसे मुंबई पुलिस ने 2007 में हुई हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया था। काजेरी को 2008 में एक सत्र अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसे जेल की सजा काटने के लिए महाराष्ट्र के नासिक सेंट्रल जेल भेज दिया गया। अधिकारी ने बताया कि 2011

में उसे 30 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था, लेकिन वह अपनी सजा पूरी करने के लिए जेल नहीं लौटा और तब से फरार था। मुंबई पुलिस ने उसकी तलाश महाराष्ट्र के नासिक, जालना, हिंगोली और परभणी तथा केरल में भी की थी, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। अधिकारी ने कहा, कई वर्षों के बाद, अपराध शाखा के अधिकारियों को काजेरी की तेलंगाना में मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी मिली, जहां से उसे आखिरकार पकड़ लिया गया। उन्होंने कहा कि काजेरी को बाद में मुंबई लाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया।

सरकार ने अंतिम एंजेल टैक्स नियमों को अधिसूचित किया

मुंबई: ओवरवैल्यूएशन पर अंकुश लगाने और पूंजी लेनदेन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, अपने उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करने वाली गैर-सूचीबद्ध कंपनियों 25 सितंबर से 30.6 प्रतिशत की दर से एंजेल टैक्स के अधीन होंगी। केंद्र ने सोमवार देर रात एंजेल टैक्स को अधिसूचित किया। निवासी और अनिवासी निवेशकों को स्टार्टअप द्वारा जारी इक्विटी और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमानीय शेयरों के मूल्यांकन के लिए नियम। जबकि पहले केवल एक निवासी निवेशक द्वारा किए गए निवेश पर एंजेल टैक्स लगता था,

2023-24 के बजट ने गैर-निवासी निवेशकों को शामिल करने के लिए इसके दायरे का विस्तार किया, जो स्टार्टअप के भीतर वित्तीय लेनदेन को विनियमित करने और सटीक मूल्यांकन आकलन सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। बजट के अनुसार, अतिरिक्त प्रीमियम को 'स्रोतों से आय' माना जाएगा और 30 प्रतिशत से अधिक की दर से कर लगाया जाएगा। हालांकि, उद्भव (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) द्वारा पंजीकृत स्टार्टअप को नए मानदंडों से छूट दी गई है। आयकर (इक्कीसवां



संशोधन), नियम, 2023, जो नियम 11यूए को संशोधित करता है, निर्दिष्ट करता है कि शेयरों का उचित मूल्य प्रदान की गई विधियों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 10 प्रतिशत सेफ हार्बर मार्जिन के हिसाब से उपरोक्त कुछ भी, कर योग्य प्रीमियम के रूप में समझा जाएगा। संशोधित नियम निवासियों के साथ-साथ अनिवासी

निवासियों से निवेश के लिए अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों (सीसीपीएस) के उचित बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए एक तंत्र पेश करते हैं। ध्रुव एडवाइजर्स के पार्टनर, पुनित शाह ने कहा, "यह भारतीय कंपनियों के शेयरों की खरीद की कीमत के लिए अनिवासी निवेशकों

(एफडीआई) को बहुत आवश्यक लचीलापन प्रदान करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। अनिवासी निवेशक, विशेष रूप से निजी इक्विटी (पीई) निवेशक विभिन्न बाहरी और आंतरिक मापदंडों के आधार पर शेयरों के परिवर्तनीय मूल्य निर्धारण के लिए भारतीय कंपनियों/प्रमोटरों के साथ अद्वितीय समझौते में प्रवेश करते हैं, जिन्हें आवश्यक रूप से बुक वैल्यू या रियायती नकदी प्रवाह विधियों द्वारा कैप्चर नहीं किया जाता है।" "ऐसी घटनाओं में, उन्हें केवल मौजूदा निर्धारित तरीकों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे बिना किसी आय के एफडीआई

प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनियों पर प्रतिकूल कर प्रभाव पड़ रहा था। उम्मीद है कि अब इसे कम कर दिया जाएगा क्योंकि एफडीआई निवेशकों के पास अब अतिरिक्त नियमों का पालन करने के लिए लचीलापन होगा।" तरीकों, "शाह ने कहा। संशोधित नियमों ने गैर-निवासियों से प्राप्त विचार के लिए मसौदा नियमों में प्रस्तावित पांच नई मूल्यांकन विधियों को बरकरार रखा है - (1) तुलनीय कंपनी एकाधिक विधि, (2) संभाव्यता भारित अपेक्षित रिटर्न विधि, (3) विकल्प मूल्य निर्धारण विधि, (4) मील का पत्थर विश्लेषण विधि, और (5) प्रतिस्थापन लागत विधि